स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–19, अंक–12, मार्गशीर्ष–पौष 2068, दिसम्बर 2011

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्रा, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा-4

स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्त्ताओं ने पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन किए और केंद्र सरकार को चेताया कि यदि देश को सबसे अधिक रोजगार उत्पन्न करने वाले खुदरा व्यापार क्षेत्र को विदेशी कंपनियों को सौंपा तो सड़क पर ईंट से ईंट बजा देंगे।

अनुक्रम

आवरण लेख
संसद ठप्प भारत बंद
सरकार का निकला दम /4

राष्ट्रीय सम्मेलन देवघर (झारखंड)
प्रस्ताव–1, 2, 3 और 4 /9–13

स्मरण
व्यर्थ न हो बलिदान (हुतात्म बाबू गेनू की संक्षिप्त जीवनी)
– मुकुंद गोरे /14

प्रतिक्रिया
रिटेल में विदेशी कंपनियों को अनमुति
– दीवान अमित अरोड़ा /16

चिंतन
खुदरा बाजार में विदेशी कंपनियों का प्रवेश
– डॉ. आशीष वशिष्ठ /18

कृषि
किसानों की त्रासदी
– देविन्दर शर्मा /21

सामयिकी
कैसे रूके रुपये का अवमूल्यन
– निरंकार सिंह /24

अर्थव्यवस्था
एक निराशाजनक नीति
– डॉ. भरत झुनझुनवाला /27

सुरक्षा
भारी कूटनीतिक भूल
– ब्रह्म चेलानी /29

पड़ताल : अमरीका डूबने की ओर. . .
– गिरीश अवस्थी /31

इतिहास और अब : शिक्षा से दूर होते विश्वविद्यालय
– उमेश प्रसाद सिंह /33

पर्यावरण : जलवायु परिवर्तन पर फिर बहस
– सुनीता नारायण /35

पाठकनामा /2

पाठकनामा

महंगाई सताने लगी अब

महंगाई पर स्वदेशी पत्रिका निरंतर कोई न कोई लेख अवश्य प्रकाशित करती रहती है लेकिन महंगाई को काबू करने वालों पर जूँ तक नहीं रेक रही है। आज पैट्रोल, डीजल, दाल, चावल, गेहूँ और आम जरूरत मंद चीजें दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही है। आज प्राइवेट सर्विस करने वाले और छोटे–मोटे अपना रोजगार करने वाले इस महंगाई से काफी बुरी तरह ग्रस्त हो चुके है। अभी बीते माह एक युवक ने केंद्रीय मंत्री शरद पावर को चाटा जड़ दिया, इससे पहले उसने संचार मंत्री सुखराम को भी इसी युवक ने थप्पड़ मारा था। देखा जाए यह सिलसिला भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी इसी प्रकार हुआ है। आखिर कारण क्या है? कोई व्यक्ति हमारे प्रिय नेताओं पर क्यों अपना गुस्सा इस प्रकार उतार रहे हैं। कायदे से यह होना चाहिए था कि आम आदमी चुनाव के दौरान इन नेताओं को वोट नहीं देता, परंतु लगता है कि अब आम आदमी का सब्र टूट गया है कि वो अब इन नेताओं से तंग आ चुका है। कारण स्पष्ट है – बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, बढ़ती हुई महंगाई। हालांकि ऐसी घटनाएं उचित नहीं है परंतु जब सरकार ही कुछ न करे तो जनता क्या करे? अब नेताओं को समझ लेना चाहिए कि जल्द से जल्द उनको महंगाई पर आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

– मनोज कुमार, शाहदरा, दिल्ली

पैट्रोल–डीजल पर गुमराह करती सरकारें

पैट्रोल महंगा हो रहा है और दूसरी तरफ इंडियन आयल और सरकारी तेल कंपनियों का मुनाफा करोड़ों में बढ़ रहा है। यह उचित है कि सरकारी कंपनियां भी कुछ प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य पैदा करें। मगर क्या यह उनका काम नहीं है कि वे कीमतों को इस स्तर पर बनाए रखें जिससे जनसाधारण को दिक्कत न हो? क्या सिर्फ सरकार ही अपने फालतू खर्च घटाएगी या हमारे औद्योगिक दैत्यों के साहब लोग भी थोड़ा साधारण आदमी की तरह रहेंगे। जहां तक तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों का सवाल है, उनमें कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। सरकार को अब प्राइवेट गाड़ियों द्वारा मनचाही मात्रा में तेल पीने पर अंकुश लगाना चाहिए साथ ही लोगों को कहिए वे हवाई जहाज से कम चलें, रेल से ज्यादा। तेल पर, सरकार की बयानबाजी है कि डालर के मुकाबले रूपए की कीमत लगातार गिर रही है, जिसके कारण तेल की कीमत बढ रही है। क्या सभी केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को तेल पर कम से कम टैक्स नहीं लगाया चाहिए। कब सरकार सोकर जागेगी, कब जनता को राहत मिलेगी – इसकी संभावना कब होगी यह किसी को पता नहीं। – राकेश कुमार दास, मीडिया अपार्टमेंट, गाजियाबाद

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

"धर्मक्षेत्र" शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 1,000 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखें)

उन्होंने कहा

भाजपा ने खुदरा क्षेत्र में सीधे विदेशी निवेश का हमेशा विरोध किया है।

– लालकृष्ण आडवाणी

सरकार द्वारा विदेशी कंपनियों को देश में खुदरा व्यापार की अनुमति को देना मैं पूर्णता विरोध करती हूँ।

– ममता बनर्जी

हम अपने प्रदेश में विदेशी कंपनियों को खुदरा व्यापार में घुसने नहीं देंगे।

– मायावती

खुदरा व्यापार क्षेत्र में विदेशी निवेश देना सरकार द्वारा लाखों लोगों की रोजी–रोटी से खिलवाड़ करने जैसा है।

– राजकुमार भाटिया, व्यापारी, दिल्ली

संपादकीय

सावधान! संघर्ष अभी बाकी है

विदेशी कंपनियों को देश में खुदरा व्यापार करने की अनुमति देने के मंत्रिमंडलीय फैसले पर भले ही जन दबाव के कारण सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। मनमोहन सिंह ने अपने कदम वापस सिर्फ इसलिए है कि उन्हें यह डर था कि यदि खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश को अनुमति देने के फैसले पर अड़े तो सरकार भी जा सकती थी। सिर्फ ममता बनर्जी ने ही कड़ा रुख नहीं दिखाया, बल्कि इस मुद्दे पर कांग्रेस भी दरकने लगी थी। सोनिया गांधी को अपनी ही पार्टी में बगावती तेवर वाले सांसद दिखाई पड़ने लगे थे। और फिर पूरा देश केबिनेट के फैसले के खिलाफ खड़ा हो चुका था। स्वदेशी जागरण मंच की आवाज पर दर्जनों संगठनों ने मिलकर एक दिन का पूरे भारत बंद का सफल आयोजन, सरकार को सोंचने पर मजबूर कर दिया। भाजपा समेत अन्य विपक्षी दलों द्वारा संसद को इस मुद्दे पर न चलने देने की रणनीति ने भी सरकार के हाथ पांव फुला दिए। प्रधानमंत्री के पास अपने तुगलकी फैसले को रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। पर सजग नागरिकों को एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि कांग्रेस की केंद्र सरकार ने राजनीतिक विवशता के कारण सिर्फ इस मुद्दे पर फिलहाल एक कदम वापस खींचे हैं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद विदेशी कंपनियों को खुदरा व्यापार करने की अनुमति देने की एक और कोशिश हो सकती है। मनमोहन सिंह देश के नागरिकों से ज्यादा अमरीकी अधिकारियों को दिए अपने वचन को निभाने के प्रति ज्यादा संजीदा हैं। उन्होंने कहा भी था कि यदि इस फैसले को वापस लिया तो देश की बड़ी फजीहत हो जाएगी। स्वदेशी जागरण मंच लगातार आगाह करता आ रहा है कि अमरीका के दबाव में सरकार गुपचुप खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश को अनुमति देने की तैयारी कर रही है। केबिनेट नोट कई माह पहले ही तैयार कर कर लिया गया था, बस चुपके से उसे केबिनेट से पास कराने की जुगत में सरकार थी। और संरकार ने इसे पास भी फुल केबिनेट में नहीं कराया, तृणमूल कोटे के मंत्रियों की उपस्थिति के बगैर यह फैसला किया गया कि खुदरा व्यवापार में 51 फीसादी विदेशी निवेश को अनुमति दी जाएगी। कांग्रेस का यह फैसला न सिर्फ संघीय ढ़ांचा वाली सरकार के मूल आधार के विपरीत था, बल्कि यह गैर संवैधानिक भी था। खुदरा व्यापर राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस पर कोई भी केंद्रीय नीति थोपने के पहले केंद्र को राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक सहमति बना लेनी चाहिए थी। लेकिन सहमति बनाने की बात तो दूर केंद्र ने इस पर राज्य सरकारों के साथ चर्चा करने की जरूरत भी नहीं समझी। यहीं नहीं इतने बड़े फैसले को लेने से पहले अन्य राजनीतिक दलों को भी भरोसे में नहीं लिया। इसे केंद्र की तुगलकी फैसला नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। कांग्रेस नेतृत्व को भी यह मालूम होना चाहिए था कि पांच करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले खुदरा व्यापार पर यदि विदेशी कंपनियों को कब्जा देने की नीति लागू की गई तो देश में कोहराम मच जाएगा। अब इसे कांग्रेस का भोलापन कहिए या फिर जानबूझ कर देश को विदेशी कंपनियों के हवाले करने की उनकी मजबूरी, पर फैसले के लागू होने की स्थिति में देश को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। वालमार्ट सरीखी कंपनियों के स्टोर आते ही लोग भूखमरी के कगार पर आ सकते थे। जब थोड़ी सी जनसंख्या वाले देश में वालमार्ट बेरोजगारी दूर नही कर पा रही है तो भारत जैसे देश में जहां अब जनसंख्या 120 करोड़ पहुंच चुकी है, वहां उनके आने से बेरोजगारी दूर कैसे हो सकती है, जब यह तर्क कांग्रेस के लोग देते हैं कि विदेशी कंपनियों के खुदरा व्यापार के क्षेत्र में आने से किसानों का भला होगा, उपभोक्ताओं का भला होगा और निर्माण कंपनियों का भला होगा, तो उनके विवके पर तरस आती है। कांग्रेस को वाल मार्ट जैसी कंपनियों को अपने यहां लूट की छूट देने से पहले अमरीका और अन्य यूरोपीय में उनके कारनामे देख कर आना चाहिए। यही वालमार्ट है, जो अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा का पैसा देने से इनकार कर देती है, यही वालमार्ट है जो अपनी महिला कर्मचारियों के साथ लिंग भेद करती है। यही वालमार्ट है जो अपने ग्राहकों के साथ अभद्रता करती है, यहीं वह मालमार्ट है जो किसानों को किसानी से हटाकर बड़ी कॉरपोरेट को खेतों पर काबिज करवाती है, यही वालमार्ट है जो पैसे के बल पर देश की सत्ता को प्रभावित करती है, यह वही वाल मार्ट है जो स्थानीय रोजगार को तेजी से निगल जाती है। उसी वालमार्ट और टेस्को को लाने की कवायद यह कह कर की जा रही है कि उनके आने से यहां किसानों को लाभ होगा, रोजगार बढ़ेगा और उपभोक्ताओं को सस्ते सामान मिलेंगे। कांग्रेस को शायद यह मालूम नहीं कि हमारा खुदरा व्यापार सिर्फ आर्थिक गतिविधियों का उपक्रम नहीं है, बल्कि इससे सामाजिक सुरक्षा भी जुड़ा हुआ है। नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराने, और उनकी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने में जितनी भूमिका किसी सरकार की है उससे हजार गुना भूमिका छोटे और मझोले खुदरा दुकानदारों की है। आज भी तीसों दिन का भोजन उधार में सिर्फ और सिर्फ छोटे खुदरा व्यापारी ही देने की हिम्मत रखते हैं। किसी कॉरपोरेट या विदेशी कंपनी की हिम्मत नहीं कि दूरदराज में काम करने वाला मनीआर्डर भेज घर की अर्थव्यवस्था चलाने वाले किसी व्यक्ति के परिवार को खाद्यान्न सुरक्षा दे सके। खुदरा व्यापार गरीब जनता द्वारा गरीब जनता के लिए चलाया जाने वाला आर्थिक कम सामाजिक उपक्रम ज्यादा है इसे छिन्न भिन्न करने की किसी भी कोशिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए।

संसद ठप चक्का जाम

विदेशी कंपनियों का करेंगे जीना हराम

24 नवंबर को जब खुदरा व्यापार में 51 फीसदी विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए केबिनेट की बैठक चल रही थी, तभी राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर जबर्दस्त उबाल आने लगा था कि सरकार आखिर देश के भविष्य का फैसला अपने जिद और प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के आधार पर कैसे कर सकती थी। उस विपक्ष के लोग सत्ता में शामिल कई प्रमुख दलों के नेताओं के सम्पर्क में थे और इस बात के लिए उन्हें सावधान कर रहे थे कि देश हित विरोधी प्रस्ताव केबिनेट से पास न हो।

स्वदेशी जागरण मंच दिल्ली प्रांत के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए

24 नवंबर को जब खुदरा व्यापार में 51 फीसदी विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए केबिनेट की बैठक चल रही थी, तभी राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर जबर्दस्त उबाल आने लगा था कि सरकार आखिर देश के भविष्य का फैसला अपने जिद और प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के आधार पर कैसे कर सकती थी। उस विपक्ष के लोग सत्ता में शामिल कई प्रमुख दलों के नेताओं के सम्पर्क में थे और इस बात के लिए उन्हें सावधान कर रहे थे कि देश हित विरोधी प्रस्ताव केबिनेट से पास न हो। सत्ता गठबंधन में शामिल दो प्रमुख दलों को यह बात समझ में आई और उन्होंने खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश के प्रस्ताव का विरोध करना शुरू कर दिया। तृणमूल कांग्रेस और डीएम कोटे के मंत्रियों

ने सरकार के भीतर इस प्रस्ताव का जबर्दस्त विरोध किया, लेकिन प्रधानमंत्री स्वयं और कांग्रेस के मंत्रियों ने इस केबिनेट के प्रस्ताव को पास करा लिया। अपने इस तुगलकी फैसले को सही ठहराने के लिए कांग्रेस ने एक साथ कई प्रवक्ताओं को झोक दिया।

कांग्रेस लोगों को यह समझाने की कोशिश करती रही, सरकार के इस फैसले से न सिर्फ देश में नई पूंजी आएगी, बल्कि किसानों, गांवों और उपभोक्ताओं को जबर्दस्त फायदा होगा। वालमार्ट और टेस्को जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के करतूतों से वाकिफ लोगों ने जब अपने तर्क सामने रखे तो सरकार की बोलती बंद हो गई। लगभग दो हफ्ते संसद ठप रही, व्यापारियों और दुकानदारों में जबर्दस्त गुस्सा भरने लगा।

अब बारी थी आंदोलन को नेतृत्व देने की, भारत और अमरीका दोनों सरकारों को यह बताने की, हम सोए हुए लोग नहीं हैं। हमारे ऊपर हमारे ही खिलाफ चीजें नहीं थोपी जा सकती। पिछले कई वर्षों से सरकार की मंशा को भांप उस पर नजर टिकाए स्वदेशी जागरण मंच ने देशहित को बलि चढ़ाने वाली कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के इस फैसले के खिलाफ हल्ला बोलने की योजना तत्काल बनाई, भारतीय मजदूर संघ, किसान संघ,

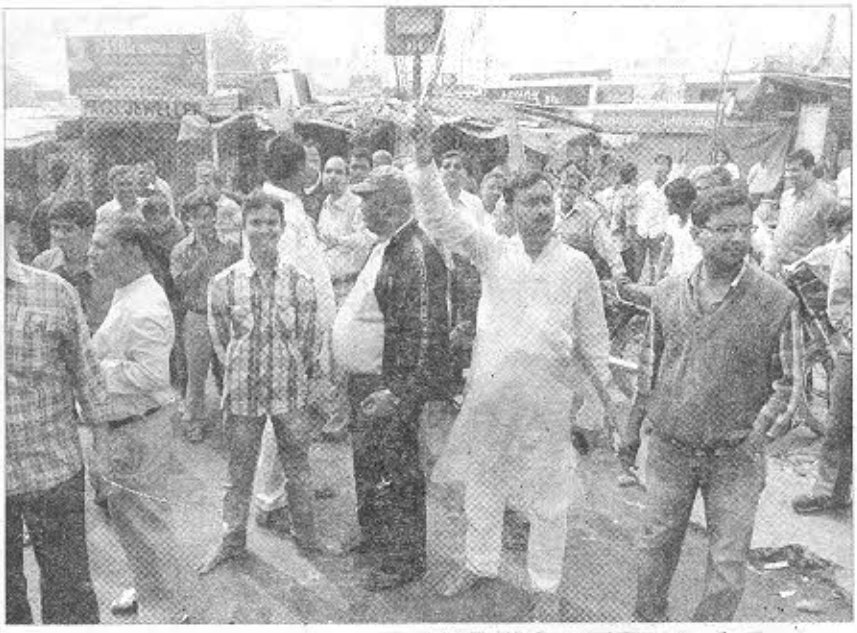

स्वदेशी जागरण मंच जमशेदपुर प्रांत के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए

व्यापारी संघ और अन्य सामाजिक संगठनों के साथ मंत्रणा कर देशव्यापी आंदोलन का कार्यक्रम तय किया। एक दिसंबर को भारत बंद का आयोजन किया गया। मंच की एक आवाज पर लाखों कारोबारियों ने बंद में हिस्सा लिया। सामान्य जन जीवन ठप हो गया। टीवी चैनलों ने पूरे दिन बंद पर कार्यक्रम चलाए। इस स्वतः स्फूर्त बंद को लगभग पांच करोड़ व्यावसायियों या व्यापारियों का समर्थन मिला।

अपनी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को परे रख लगभग सभी मजदूर संगठनों ने इस बंद को समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी, तेलगुदेशम पार्टी और वामपंथी दलों ने भी इस बंद को सफल बनाने में अपनी पूरी ताकत झोक दी। छोटे ही नहीं बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने बंद में सहयोग किया। पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और बाकी अन्य राज्यों ने भी केंद्र के इस इकतरफा फैसले के खिलाफ सड़क पर उतर विरोध जताया।

स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्त्ताओं ने पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन किए और केंद्र सरकार को चेताया कि यदि देश को सबसे अधिक रोजगार उत्पन्न करने वाले खुदरा व्यापार क्षेत्र को विदेशी कंपनियों को सौंपा तो सड़क पर ईंट से ईंट बजा देंगे। मंच के कार्यकर्त्ताओं ने प्रधानमंत्री के खिलाफ जम कर नारे लगाए और टेस्को तथा वालमार्ट के पुतले फूंके। जहां–जहां भी विदेशी कंपनियों के स्टोर खुले हैं मंच ने वहां वहां जाकर

स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्त्ताओं ने पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन किए और केंद्र सरकार को चेताया कि यदि देश को सबसे अधिक रोजगार उत्पन्न करने वाले खुदरा व्यापार क्षेत्र को विदेशी कंपनियों को सौंपा तो सड़क पर ईंट से ईंट बजा देंगे। मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के खिलाफ जम कर नारे लगाए और टेस्को तथा वालमार्ट के पुतले फूंके।

भारी विरोध जताया।

केंद्र को अपनी भूल का एहसास तब और होने लगा जब एक एक कर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने यहां यह घोषणा कर दी कि वे केबिनेट के इस फैसले को नहीं मानेंगे और अपने अपने राज्यों में कभी भी विदेशी कंपनियों को अपने स्टोर खोलने नहीं देंगे। एक तरह से राज्यों का केंद्र को यह अल्टीमेटम था कि वह संघीय ढांचे के खिलाफ जाकर काम न करे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती, बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीस गढ़ के मुख्यमंत्री रमण सिंह ने ही नहीं बल्कि कांग्रेस शासित केरल से भी यह आवाज आई कि विदेशी कंपनियों को खुदरा व्यापार में घुसने नहीं देंगे। इतने मुखर के बाद कांग्रेस के हौसले पस्त होने ही थे। उस पर भी उनके होश तब और फाख्ता हो गए जब कांग्रेस के सांसद ही केबिनेट के फैसले के खिलाफ खुले आम विरोध के स्वर उठाने लगे।

स्वदेशी जागरण मंच आध्रप्रदेश प्रांत के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए

कांग्रेस को यह अहसास हो गया कि यदि वे खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश की अनुमति वाले फैसले पर अड़े तो उनकी सरकार जानी निश्चित है। तब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने प्रणब मुखर्जी को आगे कर विरोध की लहर को कम करने की जिम्मेदारी सौंपी।

प्रणब ने सबसे पहले ममता बनर्जी को जाकर यह आश्वासन दिया कि सरकार केबिनेट के फैसले पर रोक लगाने के लिए तैयार है। फिलहाल केबिनेट के फैसले पर अमल रोका गया है। फैसले को निरस्त नहीं किया गया है। कांग्रेस अभी भी यह सोंच रही है कि उसकी राजनीतिक मजबूरी दूर होते ही इस फैसले को लागू करेंगे।

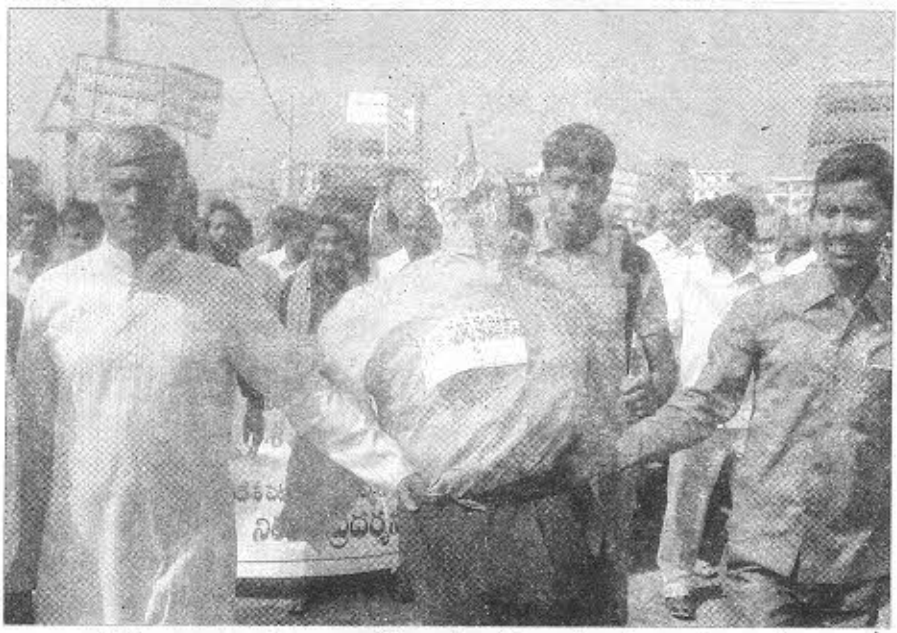

स्वदेशी जागरण मंच आध्रप्रदेश प्रांत के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए

तत्काल संकट टल गया है। कांग्रेस द्वारा रोल बैक ने थोड़ी राहत दी है। पर यह कहना मुश्किल है कि भारतीय बाजार पर गिद्ध दृष्टि जमाए अमरीका मनमोहन सिंह की सरकार को कब तक की मोहलत देती है। चूंकि यह सरकार पूरी तरह से ओबामा प्रशासन के दबाव में है इसलिए जरूरी है कि इस पर से जनदबाव न हाटे। प्रणब मुखर्जी के इस बयान से लगता है कि कांग्रेस केबिनेट के फैसले पर तत्काल रोक लगाने के लिए मजबूर सरकार की स्थिरता को ध्यान रखते हुए हुई है।

खुद प्रणब मुखर्जी अपने सांसदों को यह समझाने में लगे हैं कि यदि हम जिद पर अड़े रहते तो मध्यावधि चुनाव की आशंका उत्पन्न हो सकती थी। ❑